







# असल जिंदगी में दबाव की राजनीति का हश्त्र

ज्योति मल्होत्रा

पिछले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी और पंजाब से आई दो खबरों ने ‘दबाव बनाने’ का मतलब निस्संदेह साफ़ कर डाला है- एकदम द मर्चेंट ऑफ़ वैनिस के शाइलॉक और एंटोनियो जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ वैसा ही। पहली खबर ट्रंप के वाशिंगटन डीसी से आई ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट-2026’ को लेकर है, जिसमें भारत जैसे देशों को रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर सौ प्रतिशत तक अतिरिक्त कर लगाने की धमकी दी गई है। अगर ट्रंप ने खुद शेक्सपीयर पढ़ा होता, तो उन्हें अब तक पता चल गया होता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी अभी-अभी एक बड़ा शिखर सम्मेलन संपन्न करवा कर हटे हैं जिसमें दुनिया के तीन सबसे ताकतवर नेताओं में से दो, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, दोनों ने हिस्सा लिया था। अखबार इस बात से पटे पड़े हैं कि किस तरह पिछले छह महीनों में ईरान के खिलाफ अमेरिका-इस्राइल युद्ध शुरू होने के बाद से, भारत के कुल तेल आयात का 51 फीसदी रूस से आया है। हमारे सेनाध्यक्ष गत सप्ताह ज़्यादातर समय रूस में रहे, नए हथियारों के सौदों पर बातचीत के सिलसिले में।

अगर ट्रंप रूस-ईरान टैरिफ कानून पर साइन कर देते हैं तो उन्हें सजा लगता है कि इससे मोदी पर किसी किस्म का दबाव बन जाएगा? क्या उन्हें लगता है कि भारत डर के मारे पीछे हट जाएगा-कुछ-कुछ रोते-बिलखते और नाक सिकोड़ते हुए एंटोनियो की तरह, इससे पहले कि पोर्शिया आकर शाइलॉक का खेल पलट दे- और भारत रूस के साथ अपने बहुपक्षीय रिश्ते खत्म कर देगा? फिर यहां पंजाब में भाजपा है, जो इस सूबे में भी अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहती है, जो कि एक तरह से दबाव ही है, इस उम्मीद से कि इस सीमावर्ती राज्य के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में उसे अपना प्यार देकर नवाजेंगे। चुनाव में छह महीने बचे हैं, हर राजनीतिक दल का निशाना भी यही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस अपनी बिखरी पड़ी राज्य इकाई को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल जिला-जिला घूम रहे हैं, अपनी पार्टी में फिर से जान फूँकने की कोशिश में, ताकि भविष्य के संभावित साथी, भाजपा के साथ लेन-देन में हाथ ऊपर रखने में मदद मिल पाए। बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या पंजाब इन दिनों शतरंज खेल रहा है या अपने



भविष्य के लिए जुआ खेल रहा है। अगर यह पहला है, तो इस बड़े खेल में मोहरे कौन हैं? अगर दूसरा है, तो पत्ते किसके हाथ में हैं? तो गत सप्ताह जो बात खास रही, वह है जिस ढंग से भाजपा ने पंजाब में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पठानकोट में पगड़ी पहनकर और तलवार लहराते हुए दिखे, और पंजाबी में कुछ शब्द बोलने के साथ पार्टी की नशा-विरोधी यात्रा शुरू की; संयोगवश, नबीन और राज्य इकाई अध्यक्ष केवल ढिल्लों, दोनों ने, लिखा-लिखाया भाषण पढ़कर सुनाया। चुनाव प्रचार शुरू करने के स्थल का चयन— पठानकोट का एकता स्थल, वह यादगार जगह जहां से जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मई

1953 में जम्मू-कश्मीर में लागू तत्कालीन परमिट व्यवस्था को हटाने के वास्ते जम्मू तक की अपनी यात्रा शुरू की थी — भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुखर्जी भाजपा के शीर्ष नेताओं में एक कद्दावर हस्ती थे। पार्टी इस साल उनकी 125वीं जयंती मना रही है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खिलाफ उनका दिया नारा :‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा’ दशकों तक गूंजता रहा। जब 2019 में यह अनुच्छेद हटाया गया,तो भाजपा ने विचारधारा आधारित अपने तीन वादों में से एक को पूरा किया, जो 1980 में पार्टी शुरू होने के बाद से सदा कायम रहे (शेष दो में एक था राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और दूजा है,

समान नागरिक संहिता लागू करना—उत्तराखंड यह पहले ही कर चुका है, जबकि गुजरात, असम और मध्य प्रदेश इस राह पर हैं; ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं)।

पठानकोट में नबीन का संदेश एकदम साफ था। भाजपा पंजाब को लुभाना चाहती है, लेकिन अपनी विचारधारा की कीमत पर नहीं। सवाल यह है कि आने वाले महीनों में यह कैसे हो जाएगा। भाजपा चुनाव मिलकर लड़ने के वास्ते अकाली दल के साथ गठबंधन करेगी या नहीं? दोनों पक्षों को बखूबी पता है कि गठबंधन उनके आपसी फायदे के लिए कारगर हो सकता है— यह होने पर जहां भाजपा उम्मीदवार पंजाब के गांवों में घुसने लायक हो सकेंगे, जहां पर ज्यादातर आबादी

नेस्ले के व्यापारिक सफर की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई यह है कि वह विकसित यूरोपीय देशों के नागरिकों के लिए उच्च स्वास्थ्य मानक रखती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों के उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल अलग और हानिकारक नीति अपनाती है। एक स्विस खोजी एनजीओ की रिपोर्ट में यह पहले ही खुलासा हो चुका है कि नेस्ले अपने सबसे प्रसिद्ध शिशु आहार ब्रांड ‘सेरेलैक’ के निर्माण में दोहरी नीति अपनाता है। कंपनी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे अमीर यूरोपीय देशों में जो सेरेलैक बेचती है, उसमें ऊपर से एक ग्राम भी अतिरिक्त चीनी नहीं मिलाई जाती। इसके विपरीत, वही सेरेलैक जब भारत के माता-पिता अपने छह महीने के मासूम बच्चे के लिए खरीदते हैं, तो उसमें प्रति सर्विंग 2.7 ग्राम से तीन ग्राम तक अतिरिक्त रिफाईंड चीनी छिपी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस कहती हैं कि शिशुओं को दो साल की उम्र तक किसी भी तरह की अतिरिक्त चीनी नहीं दी जानी चाहिए। नेस्ले ने भारतीय बच्चों के स्वाद ग्रंथियों को जानबूझकर चीनी का आदी बनाया ताकि उनके उत्पाद की बिक्री लगातार बढ़ती रहे, भले ही इसके परिणामस्वरूप बच्चों में बचपन का मोटापा, दांतों की सड़न और भविष्य में डायबिटीज का खतरा पैदा हो जाए। यानी कि आज भारत में जिन बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, आप मान सकते हैं कि इसके लिए कहीं न कहीं ये एवं वन जैसी अन्य कंपनियां जिम्मेदार हैं। भ्रामक मार्केटिंग और ममता का बाजारीकरण भारत का कानून इम्पेक्ट मिलक सफ्टट्यूस्ट्स (आईएसएस) एक्ट, 1992 और एफएसएसएआई रेगुलेशन, 2020 नवजात शिशुओं के फॉर्मूला मिल्क के किसी भी प्रकार के व्यावसायिक विज्ञापन या उसे स्तनपान से बेहतर बताने वाले दावों पर पूरी तरह रोक लगाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि मां का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम है। इसके बावजूद, नेस्ले इंडिया ने भारतीय उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लिया। कंपनी ने अपने नैन एक्सेला प्रो स्टेज-1 उत्पाद पर ‘5 एचएमओ’ और ‘व्हे प्रोटीन’ के बड़े-बड़े दावे करके माताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि यह लिब्बाबंद दूध मां के प्राकृतिक दूध जैसा ही शक्तिशाली है। इसी तरह, लैक्टोइन प्रो-1के प्रचार में गैर-प्रमाणित रूप से लिखा गया कि इसका व्हे प्रोटीन ‘पचने में बेहद आसान’ होता है. एक मां अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज खरीदना चाहती है, किंतु नेस्ले ने अपनी भारी-भरकम और भ्रामक वैज्ञानिक शब्दावली के जरिए भारतीय माताओं के मन में यह भ्रम पैदा किया,



जोकि पूरी तरह से गैर-कानूनी प्रचार स्टैंट और उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। पोषक तत्वों में कटौती और गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ जब बात बच्चों या आम जनता के भोजन की हो तो शुद्धता के मानकों पर 100 फीसद खरा उतरना अनिवार्य है लेकिन नेस्ले इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उसने कई मौकों पर भारतीय मानकों को हल्के में लिया। एफएसएसएआई की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में नेस्ले इंडिया के एक इम्पेक्ट मिलक (फॉलो-अप फॉर्मूला) का सैंपल पूरी तरह मानकों से कम पाया गया है। इस प्रोडक्ट में बच्चों के दिमागी और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक विटामिन बायोटिन (बायोटिन यानी विटामिन बी-7) की मात्रा तय भारतीय कानूनी सीमा से काफी कम मिली। उपभोक्ता डिब्बे पर लिखी न्यूट्रिशन वैल्यू को सच मानकर पूरी कीमत चुकाता है किंतु डिब्बे के अंदर बंद पाउडर में वह पोषण होता ही नहीं है जिसका वादा किया गया था, वस्तुतः यह सीधे तौर पर भारतीय ग्राहकों की जेब काटने और उनके बच्चों को कुपोषण की ओर धकेलने जैसा धोखा है। भारत में नेस्ले द्वारा किए गए उपभोक्ताओं के भरोसे के सबसे बड़े कल्ल के रूप में साल 2015 का मैगी विवाद हमेशा याद किया जा सकता है।

1983 में भारत में लॉन्च होने के बाद मैगी ने भारतीय घरों में ‘दो-मिनट’ के जादुई स्लोगन से अपनी जगह बनाई थी और बाजार के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, पर जब जांच हुई तो सामने आया कि उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में मैगी के सैंपल में लेड (शीशा) की मात्रा तय सुरक्षित सीमा (2.5 पीपीएम) से कई गुना अधिक थी। लेड ईंसान के शरीर, विशेषकर बच्चों के लिवर, किडनी और मस्तिष्क विकास के लिए एक

खतरनाक न्यूट्रोऑक्सिन (धोमा जहर) है। इसके अलावा, मैगी के हर पैकेट पर लिखा होता था-‘नो एडेड एमएसजी’, मगर प्रयोगशालाओं की जांच में इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) की मौजूदगी पाई गई। इस बड़े धोखे के बाद एफएसएसएआई ने देशव्यापी प्रतिबंध लगाते हुए नेस्ले को 38,000 टन मैगी बाजार से वापस मंगाकर नष्ट करने पर मजबूर किया था और भारत सरकार ने कंपनी के खिलाफ 640 करोड़ का मुकदमा भी दायर किया था। यह आरोप सिर्फ भारतीय नियामकों का नहीं है, स्वयं नेस्ले के वैश्विक नेतृत्व ने इस सच को स्वीकार है। साल 2021 में नेस्ले के सामने आए आंतरिक दस्तावेज में कंपनी ने खुद कबूल किया कि उसके मुख्याधारा के खाद्य और पेय पोटेंफोलियो (जैसे नूडल्स, चॉकलेट, कफेक्शनरी) के 60 फीसद से अधिक उत्पाद स्वास्थ्य की स्थापित अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। कंपनी ने माना था कि उनके कुछ श्रेणियों के उत्पादों को वे चाहे जितनी कोशिश कर लें, कभी भी ‘न्यूट्रिशियस या पूरी तरह हेल्दी’ नहीं बनाया जा सकता। इसके बावजूद, भारतीय बाजारों में आकर्षक विज्ञापनों के जरिए इन उत्पादों को ‘खुशियों का प्रतिया’ और ‘बच्चों के टिफिन का सबसे अच्छ साथी’ बताकर धड़ल्ले से परोसा जाता है। ऐसे में नेस्ले इंडिया की यात्रा यह साफ दर्शाती है कि कोई भी कॉर्पोरेट ब्रांड तब तक पूरी तरह जवाबदेह नहीं बनता, जब तक कि उपभोक्ता खुद जागरूक न रहे। वस्तुतः नेस्ले द्वारा भारत में लगातार किए जा रहे ये उल्लंघन इस बात का प्रमाण हैं कि कंपनियां ढीले कानूनी मुकदमों और जुर्माने की राशियों को अपने व्यापार के खर्च का हिस्सा मान चुकी हैं। जब तक उपभोक्ता इन भ्रामक दावों को खुद नकारना शुरू नहीं करेंगे, तब तक मुनाफे का यह खेल हमारी सेहत की कीमत पर खेला जाता रहेगा।

## विचार

## टूटती मर्यादाओं व नैतिक पराभव से सिसकती इंसानियत

सुरेश सेठ

मान्यता रही है कि अगर मानवीय मूल्यों को शिरोधार्य किया जाए, तो यह जिंदगी स्वर्ग ही बन जाए। विडंबना है कि आज अंध भौतिकवाद के चलते सुख-सुविधाएं जुटाने की अंधी दौड़ में मानवता का पराभव, आदर्शों का पतन और हर गैर-कानूनी काम को कानूनी बना देने की होड़ शुरू हो गई है। आर्थिक संपन्नता के लिए हमने मर्यादा, नैतिकता और सच्चरित्रता को बिसार दिया है। क्षणिक सुख के लिए हम वह सब कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने भी नहीं की होगी। आज के दौर में सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और साहित्य व ललित कलाओं से जीवन में नवस्फुरण पैदा कर देना बीते युग की बात हो गई है। आज जो अमर्यादित है, वही इस युग की पहचान बनता जा रहा है। जब लोगों के सामने यह सच्चाई खुलकर आती है, तो मानवता शर्मसार होती नजर आती है। इन दिनों पंचांग और देश के अन्य हिस्सों में कुछ ऐसी अमानवीय घटनाएं घटी हैं, जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हाल ही में पंजाब के बठिंडा जिले के गांव भाई बख्शीर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई। यहां फसल खराब होने से परेशान होकर किसान सौदागर सिंह ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक किसान ने अर्थराइटिस के कारण टाइटैनियम धातु से बने कृत्रिम घुटने लगवाए थे। हृदयहीनता की हद तो तब हो गई, जब अंतिम संस्कार के पश्चात अस्थियां चुनने के बहाने एक नशेड़ी ने चिता से वे कृत्रिम घुटने चुराए और थैले में डालकर भागने लगा। हालांकि, परिवारवालों की सतर्कता के कारण उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। सवाल यह उठता है कि आखिर हमारी मानवीय संवेदनाएं कहाँ चली गई हैं? यह इतनी निष्कृष्ट हरकत है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि चोर अब चिताओं को भी नहीं बख्शा रहे हैं। वहाँ असम के गुवाहाटी से भी एक ऐसी वीभत्स घटना सामने आई है, जिसके बारे में कोई सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। यहां एक युवक ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी रिया तालुकदार की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया और दोनों हाथों की उंगलियां काटकर फ्रिज में छिपा दीं। मृतका का बिना सिर का शव फ्लैट में ही पड़ा रहा। जब उस बंद फ्लैट से असहनीय बदबू आने लगी, तो पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। ये ऐसी घटनाएं हैं, जिनके बारे में सोचकर ही मन सिहर उठता है और अंतरात्मा बेचैन होकर रह जाती है। आखिर हम किस समाज की रचना कर रहे हैं? यह केवल संवेदनहीनता की बात नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों के पूरी तरह बिखर जाने की दास्तान है। उदाहरण के लिए, एक लाचार पिता मृत्युशैया पर पड़ा था और उसके दो बेटे विदेश में थे। उन बेटों ने आपस में यह निर्दयी फैसला किया कि एक भाई पिता की बीमारी के समय जाएगा और दूसरा उनके दाह-संस्कार पर। इस बीच पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया; बस अंतिम संस्कार के खर्च के लिए पैसे भिजवा दिए गए। जिन माता-पिता ने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर और अपनी जमीन-जायदाद बेचकर बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए विदेश भेजा था, आज पीछे छोड़े खाली मकान उन रिश्तों की बात जोह रही हैं। अब इस विकट समस्या का स्थायी समाधान तलाशना बेहद जरूरी हो गया है। आज विदेशों में भी भारतीय युवा पीढ़ी का पहले जैसा स्वागत नहीं किया जाता। वहां के स्थानीय लोग इन्हें कम वेतन पर काम करने और अपनी नौकरियां छिनने का जिम्मेदार मानते हैं। यही वजह है कि अब हर देश उन्हें वापस भेजने के रास्ते तलाश रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत जैसे सर्वाधिक युवा आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। दुर्भाग्य से, यह बात राजनेताओं द्वारा केवल चुनावी मंंचों से ही कही जाती है। युवा यथोचित रोजगार न होने से विदेशों की ओर दौड़ रहे हैं। फलतः भारत ‘बुजुर्गों का देश’ बनता जा रहा है। सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े दावे किए गए। नई शिक्षा नीति को रोजगारपरक बनाने, देश को डिजिटल रूप से सशक्त करने और कृत्रिम मेधा के शिखर पर पहुंचाकर नए अवसर पैदा करने की बातें तो कही गईं। लेकिन ये सब महज कागजी सपने ही साबित हुए। रोजगार विहीनता के दलदल में फंसा युवा वर्ग नशे और निटल्लेपन की ओर बढ़ रहा है। यही सामाजिक और आर्थिक भटकाव अंततः उन्हें उन अमानवीय और धिनीने कृत्यों की ओर धकेल रहा है। सवाल यह उठता है कि खोखले दावों और नैतिक पतन का यह जानलेवा माहौल आखिर कब और कैसे बदलेगा?







